

## FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Sagar

No. ~~3065~~ A/FRA/2016-17/Sagar

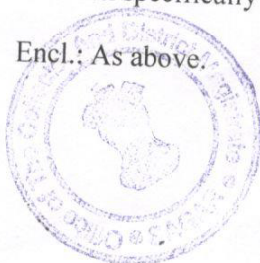
Dated 2/3/17

**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **248.76 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **WRD Div. No. 1 Sagar** (name of user agency) for **Construction of Kadan Medium Project** (purpose for diversion of forest land) in **Sagar District** falls within jurisdiction of **Ekapna-Basona and Berkheri Suvansh** village (s) in **Sagar** tehsils. It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **248.76 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s); Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District level Committee are enclosed as annexure- I to annexure-21
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and the they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Ekapna-Basona and Berkheri Suvansh** villages (s) in enclosed as annexure- I to annexure-21
- (d) The discussion and decision of such proposal had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As above.



(Vikash Narwal)  
Collector  
Sagar (M.P.)  
**COLLECTOR  
SAGAR**



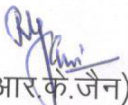
कड़ान मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि का वन अधिकार  
अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चय की कार्यवाही हेतु  
उपखंडस्तरीय वन अधिकार समिति का प्रस्ताव

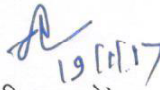
दिनांक 19.1.2017 को कड़ान मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि का वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकारों के विनिश्चय की कार्यवाही हेतु उपखंडस्तरीय वन अधिकार समिति सागर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न विवरण अनुसार अधिकारीगण उपस्थित रहे -


- 1 श्री एस.के. चंदेल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर
- 2 श्री जी.डी.बरबडे अनुविभागीय अधिकारी (वन) सागर।
- 3 श्री आर.के. जैन अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर
- 4 श्री के.के. सूर्येश सदस्य सचिव उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति सागर

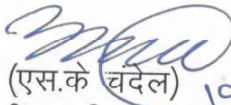
बैठक में अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर द्वारा बताया गया कि राहतगढ विकासखंड के अंतर्गत कड़ान मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में वनखंड क्र 367 की 55.86 हेक्टेयर, वनखंड क्र 368 की 75.14 हेक्टेयर एवं वनखंड क्रमांक 369 की 18.56 हेक्टेयर कुल 248.76 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है। डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत इकपना बसौना एवं बरेखेडी सुवंश का ग्राम पंचायत प्रस्ताव एवं वनक्षेत्र अधिकारी उत्तर वनमंडल सागर के प्रस्ताव के आधार पर प्रभावित भूमि में वन अधिकार पत्र धारक का हक प्रभावित नहीं हो रहा है।

समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। तदोपरांत कड़ान मध्यम परियोजना अंतर्गत वन व्यपर्वतन हेतु समिति द्वारा वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने की अनुशंसा किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

  
(आर.के. जैन)  
एस.डी.ओ जलसंसाधन  
संभाग क्र 1 सागर

  
(जी.डी. बरबडे)  
अनुविभागीय अधिकारी (वन)  
सागर

  
(के.के. सूर्येश)  
सदस्य / सचिव

  
(एस.के. चंदेल)  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  
सागर